ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

11/08/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

Ground & second floor, Orchid Mall, Boring road (Opp: A.N. College) Patna 800001

THE HINDU 11.08-2023 National

➡ मणिपुर में शांति बहाल की जाएगी, प्रधानमंत्री नेलोकसभा को आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में अपनी सरकार के अविश्वास प्रस्ताव जीतने के बाद भाषण दिया।

मणिपुर पर

उन्होंने मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया कि भारत और संसद उनके साथ है और राज्य और केंद्र सरकार राज्य में शांति और विकास वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

"मणिपुर में हिंसा दुखद है। क्रीमिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अस्वीकार्य है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं कि दोषियों को सजा दी जाए। हम मणिपुर में अपनी माताओं और बेटियों को यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह देश आपके साथ है, यह घर आपके साथ है।"

उन्होंने उदाहरणों के साथ बताया कि कांग्रेस के समय से कितनी समस्याएं बढ़ीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे उनकी सरकार ने उत्तर पूर्व के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि भाजपा के सत्ता में रहने के नौ वर्षों के दौरान उन्होंने 50 बार उत्तर पूर्व का दौरा किया है, जबकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 400 से अधिक बार दौरा किया है।

कांग्रेस पर हमला

श्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया कि पिछले वर्षों में कांग्रेस ने उत्तर पूर्व के साथ कैसा व्यवहार किया, चाहे वह इंदिरा गांधी के समय मिजोरम में बमबारी हो, चाहे 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान नेहरू द्वारा असम को उसके हाल पर छोड़ देना हो।

विपक्ष को 'अहंकारी, वंशवादी और भ्रष्ट' करार देते हुए मोदी ने कहा कि 2018 में अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए सौभाग्य लेकर आया, उन्होंने कहा, 'मैं विपक्ष से 2028 में फिर से प्रयास करने के लिए कहता हूं

विधेयक सीईसी और ईसी को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को हटाने का प्रयास करता है।

केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) को हटाने के लिए एक विधेयक पेश किया। तीन सदस्यीय पैनल में अब सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री होगा. तीन सदस्यों का चुनाव होना है।इस विधेयक के पारित होने के बाद आयुक्त में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आम तौर पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) और सीजेआई को सदस्य बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक संसद में कानून नहीं बन जाता।

विपक्ष ने सरकार पर अदालत के आदेश को कमजोर करने का आरोप लगाया।
भारतीय जीपीएस नैविक को आधार नामांकन उपकरणों से जोड़ा जाएगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा, अमेरिकी जीपीएस का भारतीय संस्करण बनाने वाली सात उपग्रह प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (एनएवीआईसी) को जल्द ही देश भर में आधार नामांकन उपकरणों में एकीकृत किया जाएगा। विभाग ने क्षेत्र के सफल उपयोग की सुविधा प्रदान की है। परीक्षण, और उपकरणों की खरीद विनिर्देश को अंतिम रूप देने में तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने का तकनीकी विवरण प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आधार नामांकन किट जिनका उपयोग व्यक्तिगत विवरण एकत्र करने और सत्यापित करने के लिए किया जाता है, जीपीएस का उपयोग करते हैं।

जम्मू-कश्मीर नेअपनी संप्रभुता 'बिल्कुल' भारत को सौंप दी: SC

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही एक संवैधानिक पीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता "पूरी तरह से" भारत के डोमिनियन को सौंप दी है।

"यह भारत के प्रभुत्व के लिए संप्रभुता का कोई सशर्त आत्मसमर्पण नहीं था। संप्रभुता का आत्मसमर्पण बिल्कुल पूर्ण था", सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा।

उन्होंने आगे कहा कि यह प्रतिबंध कि भारत सरकार कुछ हिस्सों को नहीं छू सकती है, अन्य राज्यों के समान है जिनमें राज्य के अधिकांश विषयों को केंद्र द्वारा नहीं छुआ जाता है। "लेकिन केवल इसलिए कि संसद कानून बनाते समय राज्य सूची के किसी आइटम को छूने से अक्षम है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन सभी राज्यों ने एक बार अपनी संप्रभुता भारत के डोमिनियन को सौंप दी थी"।

अदालत इस तर्क पर प्रतिक्रिया दे रही थी कि जम्मू-कश्मीर को दिया गया "विशेष स्वायत्त दर्जा" और राज्य में "अवशिष्ट विधायी शक्ति" का बरकरार रहना स्पष्ट संकेत है कि जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता का तत्व बरकरार रखा है।

जल्द ही AI आपको आवाजका उपयोग करके UPI भुगतानकरने की अनुमति देगा

यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए, RBI ने वॉयस कमांड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को सक्षम करने के लिए AI आधारित वार्तालाप सुविधाओं का प्रस्ताव दिया है।

आरबीआई ने ऑफ़लाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेनदेन सीमा को ₹ 200 से बढ़ाकर ₹ 500 करने की योजना की भी घोषणा की है।

भारत, जापान श्रीलंकाके साथ त्रिपक्षीय सहयोग फिर से शुरू करने के तरीकों पर अध्ययन कर रहा है।

श्रीलंका द्वारा पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) परियोजना के लिए संयुक्त भारत-जापान समझौता ज्ञापन को रद्द करने और जापानी वित्त पोषित लाइट रेल ट्रांजिट (एलआरटी) परियोजना को निलंबित करने के दो साल से अधिक समय बाद। भारत और जापान के साथ श्रीलंका के संबंध बेहतर हुए हैं। भारत और जापान ने श्रीलंकाई आर्थिक संकट में ऋण और ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

हाल ही में जापानी विदेश मंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया। श्रीलंका ने पिछले रद्द किए गए एमओयू पर लौटने और निलंबित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है।

एमपीसी ने दरें बरकरार रखीं, वित्त वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 5.4% किया, विकास कानजरिया बरकरार रखा।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रविवार को सर्वसम्मति से नीतिगत पुनर्मूल्यांकन को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, हालांकि इसने वित्तीय वर्ष 2024 (वित्त वर्ष 24) के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति को 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया।

"मई 2023 में 4.3% के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, हेडलाइन मुद्रास्फीति जून में बढ़ी और सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई-अगस्त के दौरान बढ़ने की उम्मीद है।" आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी के औचित्य को समझाते हुए कहा।

बेकिंग सिस्टम में ₹2000 के नोटों की वापसी सहित विभिन्न कारकों से उत्पन्न बढ़ी हुई तरलता की समस्या का समाधान करने के लिए, 12 अगस्त से शुरू होने वाले पखवाड़े से बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 10% की वृद्धि की गई है।

वन्आग ने हवाईशहर को तबाह कर दिया, जिसमें कम से कम 36 लोग मारे गए।

जंगल की आग में कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई है, तेजी से बढ़ रही जंगल की आग ने एक ऐतिहासिक हवाईयन शहर को राख में बदल दिया है। आग माउई द्वीप पर लगी जिस पर लाहिना शहर स्थित है। पर्यटन के आधार पर शहर की आबादी लगभग 12000 मिलियन है।

आग सोमवार को शुरू हुई, जिससे हजारों एकड़ भूमि झुलस गई, जिससे माउई में लगभग 35000 लोगों के घर और व्यवसाय खतरे में पड़ गए। शुष्क और तेज हवाओं ने जंगल की आग को बढ़ावा दिया। अमेरिकी अग्निशमन कर्मी और तट रक्षक आग बुझाने और लोगों की जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली भंग

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने अनिवार्य अवधि से तीन दिन पहले औपचारिक रूप से नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त होने तक प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है.

इक्वाडोर में रैली के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या।

इक्वाडोर के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की राजधानी क्विटो में एक रैली से निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। फर्नांडो विलियाविसेनियो एक भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा हैं, जिन्होंने धमकी मिलने की शिकायत की थी, जब वह एक अभियान चलाने के बाद क्विटो में एक स्टेडियम से बाहर निकल रहे थे, तो उनकी हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति गुइलेमारो रासो ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और हत्या के लिए संगठित अपराध को जिम्मेदार ठहराया है।

इक्वाडोर में 20 अगस्त को चुनाव होंगे।

अमेज़न को बचाने के रोड मैप के साथ बैठक समाप्त

ब्राजील का अमेज़ॅन शिखर सम्मेलन बुधवार को उष्णकटिबंधीय वर्षावन की रक्षा के लिए एक रोड मैप के साथ समाप्त हुआ, जिसका जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया गया था, लेकिन कुछ पर्यावरणविदों द्वारा वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए मांगी गई ठोस प्रतिबद्धता के बिना।

अमेज़ॅन के आठ देशों के नेताओं ने मंगलवार को ब्राज़ील के बेलाम में एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें अमेज़ॅन की चल रही समाप्ति को "बिना वापसी के बिंदु तक पहुंचने से" रोकते हुए अपने देशों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई।

आठ देश बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेज़ुएला नव पुनर्जीवित अमेज़ॅन कॉर्पोरेशन संधि संगठन (एसीटीओ) के सदस्य हैं। समूह को उम्मीद है कि नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले सीओपी 28 में उसे प्रमुख आवाज मिलेगी।

रूसी और कनाडाई ठंडे क्षेत्र के बाद अमेज़ॅन वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक है। यह ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन के लिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है।

अमेरिका ने चीन में निवेश पर अंकुश लगाने का आह्वान किया

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसका उद्देश्य चीन में संवेदनशील उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कुछ अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करना है। नए नियम उन्नत सेमीकंडक्टर और क्वांटम सूचना प्रौद्योगिकियों में नई निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी और संयुक्त उद्यम निवेश पर रोक लगाते हैं।

चीन के विदेश मंत्री ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे "वैश्वीकरण विरोधी और पतनशीलता में शामिल होने" का प्रयास बताया और चेतावनी दी कि चीन दृढ़तापूर्वक अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा।

ईरान की जेल से 5 अमेरिकी नागरिक बाहर आये

ईरान ने पांच अमेरिकियों को जेल से नजरबंद कर दिया है। यह कदम संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेहरान और अमेरिकी समझौते पर विचार के बाद उठाया गया है। इसमें ईरान को दक्षिण कोरिया में जमा उसके अरबों डॉलर मिल जायेंगे.

Editorial 1

जोखिम भरा कोर्स

आने वाले महीनों में आरबीआई की मुद्रास्फीति से लड़ने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा

संपादकीय के बारे में

संपादकीय हालिया मौद्रिक नीति बैठक (एमपीसी) के बारे में है जिसमें हालांकि नीति दर में बदलाव नहीं किया गया है लेकिन मुद्रास्फीति दर को संशोधित किया गया है। बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात में भी वृद्धि की गई है। संपादकीय इनके पीछे के कारण के बारे में बात करता है।

एमपीसी की हालिया बैठक के बारे में

एमपीसी ने अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित मुद्रास्फीति दर में 30 आधार अंक की वृद्धि हुई है, पहले मुद्रास्फीति दर 5.1% अनुमानित थी, इसे बढ़ाकर 5.4% कर दिया गया है। इसका कारण टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी बताया गया है जिससे झटका लग रहा है। जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए अनुमान को 100 आधार अंक बढ़ाकर 6.2% कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हालिया झटके ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों को अस्थिर कर दिया है।

अन्य निर्णयों केबारे में

RBI ने बैंकों के लिए कैश रिजर्व रेशियो CRR भी 10% बढ़ा दिया है। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 8 सितंबर की बैठक में इसकी समीक्षा की जाएगी.

एमपीसी एक 6 सदस्यीय आरबीआई पैनल है जो रेपो रेट, सीआरआर आदि जैसी नीतिगत दरों में बदलाव पर निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर बैठक करता है।

Editorial 2

आवास कीजरूरत है

बाघों केरहने लायक आवास में सुधार करना उनकी संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है

संपादकीय के बारे में

संपादकीय में बाघों के नए अनुमानों के बारे में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के हालिया अपडेट के बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि कुछ राज्यों में बाघों की संख्या क्यों बढ़ी है, इन राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। यह आगे बताता है कि बाघ संरक्षण को ठीक से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है

WIL का ताज़ा अनुमान क्या कहता है

मध्य प्रदेश में आठ वर्षों में दूसरी बार 785 बाघ या बाघों का लगभग पांचवां हिस्सा रिपोर्ट किया गया है। राज्य में पिछली जनगणना के बाद से बाघों की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है।

एमपी नेबाघ संरक्षण को कैसे बेहतर बनाया है?

एमपी ने पिछले कुछ वर्षों में शिकारियों और शिकारियों की आबादी को संतुलित करने के लिए बाघों के साथ-साथ उनके शिकार दोनों को राज्य के भीतर सक्रिय रूप से स्थानांतरित करने के दृष्टिकोण में सुधार किया है। कई शिकार हटा दिए गए हैं और नए प्रकार के शिकार पेश किए गए हैं। बारासिगा को सतपुड़ा और बांधवागढ़ में पेश किया गया है। चीतल को सतपुड़ा और संजय गांधी बाघ अभयारण्य में पूरक बनाया गया है।

भारत का संरक्षण लोकाचार और आगे का रास्ता

भारत का संरक्षण लोकाचार हमेशा बाघों की संख्या बहाल करने का रहा है। वह तरीका जो मनुष्यों के साथ इसके सह-अस्तित्व का पक्ष ले सकता है। अब चुनौती वन संरक्षण के तहत वन भूमि में कमी की है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक राज्य विशेषज्ञों की निगरानी में सक्रिय शिकार प्रबंधन लागू करें।